

प्रयाग

दर्पण

वर्ष : 08 अंक : 151 प्रयागराज,शनिवार 10 सितम्बर , 2022 हिन्दी दैनिक पृष्ठ—4 मूल्य : 3 रुपया

जौनपुर में बोले योगी, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति कुर्क कर गरीबों के उपयोग में लाएगी सरकार

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ने तय किया है कि भ्रष्टाचारी की संपत्ति को कुर्क करके सार्वजनिक उपयोग में लाया जाये, जिससे इसका इस्तेमाल गरीब कल्याण के कार्यों भी हो सके। योगी ने शुक्रवार को यहां लगभग 250 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकेगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति जुटाई है, उसे कुर्क करके उसका सार्वजनिक उपयोग किया जाएगा और गरीबों के उपयोग में भी लाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने यहां स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित ात करने से पहले 258 करोड़ रुपये की लागत वाली 116 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।



इसके बाद उन्होंने निर्माणधीन मेडिकल कॉलेज के साथ ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये। यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां दंगा करने वाले जेलों में भेजे गये हैं। उन्हें एहसास कराया गया है कि दंगा कराने का परिणाम

उन्हें तुरंत मिलेगा। इसके लिए सरकार ने कानून भी बना दिया है। योगी ने दावा किया कि पिछले पांच सालों से उनकी सरकार अपराध और अपराधि यों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी ये स्वीकार हुआ कि ने उत्तर प्रदेश अब दंगामुक्त प्रदेश बन चुका है। उप्र के इस मॉडल को देश में अन्य राज्यों ने भी स्वीकार किया है। योगी ने कहा कि ब्रिटेन ने भारत

पर 200 साल राज किया था। आज वही भारत अपनी आजादी के 75 वर्षों में उसी ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार लगा कि स्वा्ध णीनता दिवस का पर्व सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें जन-जन की भागीदारी हुयी है। मुख्यमंत्री योगी ने स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए ‘पंच प्रणश से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम लक्षित संकल्पों से जुड़कर अपने अपने क्षेत्र के दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि चाहे वह छात्र हो, शिक्षक, किसान, उद्यमी, व्यापारी या समाज का कोई भी तबका हो, सबके मन मे ‘देश प्रथमश का भाव होना चाहिए। उन्होंने कहा, “पीएम मोदी के पंच प्रण किसी व्यक्ति, मजहब, धर्म या क्षेत्र के चुका है। उप्र के इस मॉडल को देश में अन्य राज्यों ने भी स्वीकार किया है। योगी ने कहा कि ब्रिटेन ने भारत

गोवा में ‘कर्लीज रेस्तरां पर चला बुलडोजर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरी गोवा के अंजुना में ‘कर्लीज रेस्तरां का एक हिस्सा ढहाए जाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। यह रेस्तरां भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद हाल में सुर्खियों में आया था। न्यायालय का यह आदेश एक खास सर्वेक्षण संख्या पर आधारित ढांचों को गिराए जाने से ही संबंधित है। सर्वेक्षण संख्या भूमि के एक टुकड़े को आवंटित एक विशिष्ट संख्या या पहचान होती है। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली एक पीठ ने यह स्पष्ट किया कि विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या के अलावा किसी और जमीन पर बने अवै 1 ढांचे गिराए जा सकते हैं। पीठ ने ‘कर्लीज रेस्तरां और बार मालिक को फिलहाल वाणिज्यिक गतिविधियां रोकने का भी निर्देश दिया। इससे पहले, गोवा सरकार ने तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए रेस्तरां को गिराए जाने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी थी। सोनाली फोगाट अपनी मौत से कुछ



घंटों पहले इस रेस्तरां में पार्टी करते हुए दिखायी दी थीं। सोनाली की मौत के मामले में गिरफ्तार पांच लोगों में रेस्तरां के मालिक एडविन नूस भी शामिल थे, जिन्हें बाद में जमानत दे दी गयी। रेस्तरां के मालिक को जीसीजेडएमए के 2016 के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिाकरण (एनजीटी) से कोई राहत नहीं

मिली थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गयी। एनजीटी अ्क यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल ने छह सितंबर को इस मामले पर सुनवाई की थी। जिला प्रशासन ने के बृहस्पतिवार को एक नोटिस जारी कर अपने ध्वस्तीकरण दल को शुक्रवार को रेस्तरां इमारत ढहाए जाने का आदेश दिया था।

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक की लहर, राजकीय शोक शुरू

लंदन। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल स्थित आवास पर निधन के एक दिन बाद शुक्रवार को ब्रिटेन में राजकीय शोक जारी है और इस बीच पूरे देशभर से लोग महारानी के आवास के इर्द-गिर्द श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग चुका है। लंदन के बकिंघम पैलेस और बर्कशायर में विंडसर कैसल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गयी, जिसमें कई लोगों ने 70 साल तक राज करने वाली महारानी के निधन पर अश्रुपूरित नेत्रों से निजी श्रद्धांजलि दी। महारानी एलिजाबेथ-द्वितीया का निधन 96 वर्ष की उम्र में कल हो गया। राष्ट्रमंडल के महासचिव बैरोनेस पेट्रीसिया स्कॉटलैंड ने कहा, “1953 में महारानी ने राष्ट्रों के समूह को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया, जिसकी तुलना श्अतीत के साम्राज्यों से नहीं की जा सकती। अपने शासनकाल की शुरुआत में राष्ट्रमंडल के लिए महारानी की परिकल्पना उनके समर्पण और प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर पूरी हुई है।”



राष्ट्रमंडल सचिवालय के पास से लेकर बकिंघम पैलेस तक जाने वाले मार्ग में महारानी को श्रद्धांजलि देने के लंदन ब्लैक कैब को एक के बाद एक पंक्तिबद्ध खड़ा किया गया था, जिनकी से नहीं की जा सकती। अपने शासनकाल की शुरुआत में राष्ट्रमंडल के लिए महारानी की परिकल्पना उनके समर्पण और प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर पूरी हुई है।”

वंशानुगत राजशाही उनके बेटे और उत्तराधिकारी किंग चार्ल्स तशतीय के पास गई है, जो अपनी पत्नी क्वीन कंसोर्ट कैमिला के साथ दिवंगत महारानी को लेकर बाल्मोरल से लंदन लौटेंगे। किंग चार्ल्स ने एक बयान में कहा, “हम स्नेहिल महारानी और एक बहुत प्यारी मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे पता है कि उनके निधन को पूरे देश, क्षेत्र और

राष्ट्रमंडल तथा दुनिया भर के अनगिनत लोगों द्वारा गहराई से महसूस किया जाएगा।” किंग चार्ल्स शुक्रवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस के साथ पहली बार दर्शकों के बीच आएंगे और उसके बाद एक संयुक्त संसद सत्र में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है यह पूरे दिनभर चलकर स्थानीय समयानुसार रात 10 बजे तक जारी रहेगा। संसद की 10 घंटे की बैठक पूरी तरह से महारानी पर केंद्रित होगी। मध्य लंदन में, दिवंगत महारानी को 96 राउंड तोपों की सलामी के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें से प्रत्येक राउंड महारानी के जीवन के एक-एक वर्ष को समर्पित होगा। चर्च अपनी घंटी भी बजाएंगे। इंग्लैंड के चर्च ने पूरे देश के विभिन्न चर्च को प्रार्थना या विशेष सेवाओं के लिए खोलने को लेकर प्रोत्साहित किया है। ट्रस और वरिष्ठ मंत्री मध्य लंदन में सेंट पॉल कैथेड्रल में सार्वजनिक स्मरति सेवा में भाग लेंगे और उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि राष्ट्रीय शोक की अवधि कितने दिनों की होगी।

कुल्छू में पश्चिम बंगाल के 4 पर्वतारोही लापता

शिमला। हिमाचल प्रदेश के कुल्छू जिले में मारुट अली रत्नी टिब्बा की चढ़ाई करने वाले पश्चिम बंगाल के चार पर्वतारोही लापता हो गए हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के निदेशक सुदेश मोख्ता ने बताया कि चारों पर्वतारोहियों की पहचान अभिजीत बानिक (43), चिन्मय मंडल (43), दिबाबा दास (37) और बिर्नॉय दास (31) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि पर्वतारोही बुधवार को लापता हो गए थे। मोख्ता ने बताया कि एक रसीडूया और अभियान के दो सदस्य मलाणा के पास वाक्रेम लौट आए थे और अधिकारियों को चार लापता लोगों के बारे में सूचित किया। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान मनाली से लापता पर्वतारोहियों की तलाश के लिए बचाव दल को इकट्ठा किया गया है।

मनाली के उप-मंडल मजिस्ट्रेट ने इस दल के साथ जरी में एक स्थानीय बचाव दल को भी भेजा है। उन्होंने कहा कि बचाव दल को प्रभावी और त्वरित कार्रवाई के लिए सैटेलाइट फोन के साथ रवाना किया गया है।

जयशंकर, राजनाथ सिंह ने जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की

तोक्यो। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा से शुक्रवार को मुलाकात की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के हितों और नीतियों के निकट समन्वय की महत्ता को रेखांकित किया। सिंह और जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा और रक्षा मंत्री हमदा यासुकाजु के साथ बृहस्पतिवार को ‘टू प्लस टू’ वार्ता’ में भाग लिया था।

जयशंकर ने टवीट किया, “हमारी ‘टू प्लस टू’ बैठक के बाद प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा से बात करके खुशी हुई। भारत और जापान के हितों एवं उनकी नीतियों के बीच निकट समन्वय के महत्व को रेखांकित किया।” उन्होंने कहा कि बैठक में भरोसा जताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किशिदा ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर जो रुपरखा तैयार की है, उसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा। सिंह ने टवीट किया कि भारत और जापान के बीच साझेदारी की क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका होगी। सिंह ने



इस बैठक के दौरान जापान के पूर्व प्र्धानमंत्री शिंजो आबो के निधन पर शोक व्यक्त किया। आबो का एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान गोली मारे जाने के हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत ने आक्रामक चीन को रोकने के एक स्पष्ट प्रयास के तहत “जवाबी हमले की क्षमताओं” सहित रक्षा बलों के विस्तार और आधुनिकीकरण की जापान को योजनाओं को भी अपना समर्थन दिया।

क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच दोनों देशों की विशेष द्विपक्षीय रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी एक स्वतंत्र, मुक्त और कानून-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत ने आक्रामक चीन को रोकने के एक स्पष्ट प्रयास के तहत “जवाबी हमले की क्षमताओं” सहित रक्षा बलों के विस्तार और आधुनिकीकरण की जापान को योजनाओं को भी अपना समर्थन दिया।

राजपथ अंग्रेजों का दिया नहीं, नाम बदलने की क्या जरूरत थी : मलिक

रोहतक। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजपथ का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं, तो उन्होंने इसका भी कर दिया। किसानों का मुद्दा उठाते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि ‘ये किसान कौम है, जो 300 साल तक कुछ नहीं भूलती, अभी एमएसपी कानून दे दीजिए, वरना एक बार फिर आंदोलन होगा। शुक्रवार को रोहतक पहुंचे राज्यपाल मलिक ने नांदल भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में खाप पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। सत्यपाल मलिक ने कहा कि एमएसपी की बात नहीं मानी गयी तो किसानों और सरकार के बीच लड़ाई होगी, मैं उस लड़ाई में राज्यपाल पद से



इस्तीफा देकर कूद पड़ूंगा। राज्यपाल ने अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि किसान और जवान खुशहाल नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। उन्होंने कहा, देश में आज किसानों और जवानों पर भारी संकट है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब फौज को बर्बाद करने के लिए अग्निवीर योजना ले आए हैं, इससे

कोई नतीजा नहीं निकलेगा। राज्यपाल ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो ईडी, इनकम टैक्स वाले आ जाते, लेकिन रिटायर होने के बाद ओरों की जांच कराऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं श्रीनगर के दो मामलों के लिए प्रधानमंत्री के पास गया था। दोनों गलत थे, कैंसिल कर दिए। मुझे डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ रुपए रिश्तत की

पेशकश हुई थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पांच कुर्ते-पायजामे में आया था और उसी में चला जाऊंगा। राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में मलिक ने कहा, एमएसपी को लागू न करने के बहुत सारे कारण हैं।

राहुल गांधी की 42 हजार की टीशर्ट पर बीजेपी ने कसा तंज, लिखा- भारत देखो

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस की “भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो टी-शर्ट पहनी थी उसकी कीमत 41,000 रुपये से अधिक है। भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दो तस्वीरें साझा कीं और राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी की ओर से जारी एक तस्वीर राहुल गांधी की है जबकि दूसरी तस्वीर में एक टी-शर्ट को उसकी कीमत के साथ दिखाया गया है जोकि गांधी द्वारा पहनी गई टी-शर्ट जैसी दिख रही है। तस्वीरें साझा करते हुए भाजपा ने टवीट किया, “भारत देखो। भाजपा ने दावा किया कि इस टी-शर्ट की कीमत 41,257 रुपये है। वहीं, कांग्रेस नेता के समर्थन में भी कुछ उपयोगकर्ताओं ने टवीट किये। एक उपयोगकर्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा के इस तरह के टवीट से पता चलता है कि इस यात्रा से वह “घबरा गई है। एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा गांधी अपने कपड़ों पर जो खर्च कर रहे हैं, वह जनता का पैसा नहीं है। यात्रा के दौरान राहुल गांे पि ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा था कि वह यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं और केवल इसका हिस्सा हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर बोले राहुल- मैंने निर्णय ले लिया है, इंतजार करें कन्याकुमारी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने संबंधी सवाल पर शुक्रवार को कहा, “मैंने निर्णय ले लिया है, मैं बहुत स्पष्ट हूँ, जब पार्टी के चुनाव होंगे तब जवाब दूंगा। तब तक इंतजार करिए। अगर मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ता हूँ, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और तब मैं जवाब दूंगा कि मैंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। उन्होंने यहां ‘भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से कहा कि पदयात्रा यह समझने की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है और साथ ही यह भाजपा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई की कोशिश है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को बचाने के लिए यह यात्रा किए जाने के आरोपों पर कहा, भाजपा-आरएसएस अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोगों से जुड़ने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं।

राजभर को फिर लगा बड़ा झटका, 75 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी

मऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र राजभर के पार्टी छोड़ने के बाद से लगातार एक-एक करके पार्टी छोड़ने का कार्यक्रम जारी है। सूत्रों की मानें तो पार्टी जिलाध् यक्ष रामजीत राजभर समेत अब तक 75 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कार्यकर्ताओं को आरोप है कि राजभर मिशन से भटक गए हैं। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौका देख पार्टी को बेचने का काम कर रहे हैं। पदाधिकारियों से कोई राय नहीं ली जा रही है। जब मन में आया तो मौका देख गठबंधन कर लिया। घर के लोगों को बड़ावा दिया जा रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर धनवानों को टिकट दिया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उन्होंने जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे के इशारे पर कार्य कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते है। जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बता दें कि ओमप्रकाश राजभर और अखिलेश के गठबंधन टूटने के बाद से राजभर अपने नए गठबंधन की तलाश में हैं। सपा से गठबंधन टूटने के बाद राजभर मायावती से गठबंधन की बात कही थी।

सम्पादकीय

शौक के जोखिम

एक खबर के मुताबिक, एक इमारत में लिफ्ट के बाहर कुत्ते ने बच्चे को काट लिया और उसकी मालिक ने बच्चे के बचाव में कुछ नहीं किया। जबकि कुत्ते के काटने पर बच्चा उस महिला के सामने कराहता रहा। अक्सर बड़े शहरों में अमीर लोगों को कुत्ता पालने का शौक रहता है, पर वह कुत्ते को घुमाने—फिराने के सिवा कुछ भी नहीं सिखाते हैं। तंपजमद इल जनसत्ताय एक खबर के मुताबिक, एक इमारत में लिफ्ट के बाहर कुत्ते ने बच्चे को काट लिया और उसकी मालिक ने बच्चे के बचाव में कुछ नहीं किया। जबकि कुत्ते के काटने पर बच्चा उस महिला के सामने कराहता रहा। अक्सर बड़े शहरों में अमीर लोगों को कुत्ता पालने का शौक रहता है, पर वह कुत्ते को घुमाने—फिराने के सिवा कुछ भी नहीं सिखाते हैं। लिफ्ट के पास महिला उस कुत्ते के साथ थी। उसी लिफ्ट में स्कूली बच्चा भी आया। तब उस बच्चे को देखकर कुत्ता न केवल भौंका, बल्कि फिर उसने उसे काट भी लिया। बच्चा महज दस साल का था। अपना बचाव नहीं कर सका। तब हमारा यही कहना है कि कुत्ते की मालिक महिला की जिम्मेदारी थी कि वह अपने कुत्ते को बच्चे से दूर रखती और बच्चे को भी उससे दूर रहने के लिए सावधान करती। पर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए सारा दोष कुत्ते की मालिक का ही माना जाना चाहिए। फिर एक ही बिल्डिंग में रहने के कारण उस महिला को उस बच्चे के प्रति तो अवश्य सुरक्षा का भाव रखना था। सवाल है कि कुत्ता पालने वाले किसी व्यक्ति के भीतर की सामान्य और बुनियादी ईंसानी संवेदना उसे समय में कहां चली जाती है और क्यों चली जाती है? एक पशु को प्यार करने और उसका खयाल रखने वाले लोग किसी तबके या ईंसान के प्रति इतने संवेदनहीन कैसे और क्यों हो जाते हैं? कहा जा रहा है कि कुत्ते का टीकाकरण हो गया था, पर इससे क्या होता है? बच्चे को कुत्ते ने जिस तरह काट लिया और जखमी कर दिया उसका जवाबदेह कौन होगा? इसलिए आज बढ़ती आबादी के माहौल में जहां आज ईंसानों का रहना भी काफी मुहाल हो रहा है, ऐसे में जानवर, विशेष रूप से कुत्ता पालना अनुचित ही माना जाना चाहिए। इनकी देखभाल करना आज काफी मुश्किल एवं परेशानी का सबब है। महानगरों में जहां आज बड़ी-बड़ी इमारतों में आम नागरिक रहते हैं, जगह की वैसे भी काफी कमी महसूस की जाती है, जहां कुत्ते को घुमाने—फिराने तक की जगह नहीं मिलती है। इसलिए घरों एवं सोसाइटी में कुत्ते पालना आज काफी दुष्कर है। ऐसे में फिर ये कुत्ते किसी को काट ले तो वह तो काफी दुख की बात ही कही जाएगी।अक्सर सोसाइटी में खेलते बच्चे इन कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा, ऐसी खबरें भी अक्सर आती रहती हैं कि किसी बच्चे को या बुजुर्ग को आवारा कुत्तों ने काट लिया या नौच कर मार डाला। बड़े शहरों—महानगरों में कुत्ते पालने के लिए नगर निगम को कई तरह के कड़े नियम भी बनाने चाहिए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका लाइसेंस जरूरी है।

डॉक्टरों को समाज और लोगों की चिंताओं को पहचानना होगा

चिकित्सा एक पेशा नहीं बल्कि एक जुनून है। इसकी गरिमा को बनाए रखने और लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने जिनैवा की घोषणा को तिर्तंबर 194८ में अपनी दूसरी महासभा में अपनाया था। यह घोषणा मानवीय लक्ष्यों के लिए एक चिकित्सक के समर्पण पर प्रकाश डालती है। जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में किए गए चिकित्सा अपराधों के महेनजर यह घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। इस घोषणा के अनुसार डॉक्टर प्रतिबद्ध है और घोषणा करता है, श्रें मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की शपथ लेता हूं, मैं मानव जीवन के अत्यंत सम्मान बनाए रखूंगा, मैं उम्र, बीमारी या विकलांगता, पंथ, जातीय मूल, लिंग, राष्ट्रीयता, राजनीतिक संबद्धता, नस्ल, यौन अभिविन्यास, सामाजिक स्थिति या किसी अन्य कारक के विचारों को मेरे कर्तव्य और मेरे रोगी के बीच हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा।चिकित्सा कार्मियों को हर कदम पर समाज और सामाजिक सरोकारों के साथ अपनी पहचान बनानी होगी। रुडोल्फ विरचो,

राज पथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। देर से ही सही पर अब सरकार को याद आ गया है कि अब तक वह राज कर रही थी अब शायद सेवा करेगी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। विपक्ष को भी भान हो गया है कि अगर अब भी उसकी चेतना का बिगुल नहीं बजा तो फिर उसका पाताल लोक में चला जाना तय है। नतीजतन, एक तरफ विपक्ष के सारे नेता नीतीश कुमार समेत सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं और राहुल गांधी श्भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। देश में यह आदर्श स्थिति हो सकती है जब पक्ष और विपक्ष यूं कमर कस कर तैयार रहेंय लेकिन क्या वाकई ऐसा है? देश में हालात पहले भी विकट रहे हैं तब नीतीश कुमार के राजनीतिक पुरखों ने कौन सी भूमिका ली थी और क्या वर्तमान विपक्ष भी उसी दिशा में है, जानना दिलचस्प होगा।भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया हर वक्त उस ढीली गैद का इंतजार करता है जब वह छक्का जड़ अपने आकाओं को खुश कर सके।

आलोचना के लिए सत्ता पक्ष के पास पाकिस्तान भेज देने से ज्यादा नया कुछ नहीं है। उसे अपनी टिप्पणियों में और नया होना होगा। एक पूर्व मंत्री फिर अवतरित हो गए हैं। वे राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि आपने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था, बालाकोट की गवाही मांगी थी और कोंवड़ महामारी के समय जब प्रधानमंत्री मोदी देश को एक कर रहे थे तब पूछा था कि थाली पीटने से क्या होगा? जाहिर है कि सत्तापक्ष तिलमिलाया हुआ है लेकिन विरोध की



जरूरतें जैसे स्वच्छ हवा, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त सीवरज सुविधाएं हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। यदि जिनैवा घोषणा को आदर्श रूप से व्यवहार में लाना है, तो एक चिकित्सक को इन मुद्दों पर संलग्न होना चाहिए। यह चिकित्सा पेशे का श्रेय है कि इसने कन्या भ्रूण हत्या को खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को धूम्रपान और शराब के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया। कई डॉक्टर बीमारों और कमजोरों की सेवा के लिए संघर्ष के क्षेत्रों में गहराई तक जाकर



आड़ और अदा वही पुरानी है। नएपन की दरकार यहां भी है क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है और इस विविधता वाले भारत में हर आठ कोस पर भाषा और पहनावा बदल जाता है। भारत जोड़ो यात्रा किस कदर जरूरी है, इसकी तसदीक यात्रा के आसपास हो रही घटनाएं भी कर रही हैं। मंगलवार को अमिताभ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को उज्जैन में महाकाल के दर्शन से वंचित कर दिया जाा है। बजरंग दल को यह बात पसंद नहीं आई कि कभी किसी समय राजबीर कपूर ने कहा था कि मटन, पाया, बीफ, रेड मीट उन्हें बहुत पसंद है। हालात ऐसे ही हैं कि कोई भी संगठन किसी भी बात पर किसी के भी बुनियादी हक़ छीनने लगता है। आप यह मत खाओ, आप इनसे शादी मत करो, आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आप ऐसा मत लिखो! यानी वे मौलिक

हक़ जो हमें हमारे संविधान से मिले हैं उन्हें लगातार छीनने की कोशिश। यह हौसला आखिर कहां पनपता है और इसे हवा कौन दे रहा है, यह अब जनता समझ चुकी है। विविधताओं के भारत में सबको एक जैसा बनाने के इस गैर संवैधानिक काम को करने वाले कभी किसी दौर में अपराधी माने जाते थे लेकिन अब ये सब हरकतें संगठन करते हैं, नियोजित तरीके से और सरकार का उन पर हाथ होता है। त्रस्त और अकेली जनता बेसब्री से चाह रही है कि कोई उनकी दबी आवाज को जुबां दे, उनके कामकाज के पुराने दिन लौटाए और यह तोड़-फोड़ की सियासत बंद करे। बिस्कुल जरूरी नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा हालात को पूरी तरह बदल पाए लेकिन सहमे हुए भारत को आवाज जरूर मिल सकती है। राहुल गांधी को भी हर बार श्हम दो हमारे दोश

चिकित्सकों (आईपीपीएनडब्ल्यू) ने परमाणु युद्ध के जलवायु परिणामों पर वैज्ञानिक अध्ययन किया है और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुखर रूप से आह्वान किया है। यह परमाणु हथियारों के निषेध (टीपीएनडब्ल्यू) पर संधि पारित करने में सहायक था। दुर्भाग्य से आज दुनिया के बड़े हिस्से में शांति और स्थिरता खतरे में है। विश्व स्तर पर ऐसी ताकतें हैं जो हथियार बेचकर भारी मुनाफा कमाने के इरादे से बाहरी और आंतरिक संघर्ष पैदा करने के लिए तैयार हैं। ऐसी ताकतें हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक और जातिगत संघर्ष पैदा करने के लिए बाहर हैं। समाज को इस तरह के खतरे से निजात दिलाने में डॉक्टर प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसे निहित स्वार्थों द्वारा समाज में प्रचलित लिंग, जाति, धर्म और अन्य सबसे महत्वपूर्ण है। हिंसा की रोकथाम एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन गया है। इसकी रोकथाम के लिए वैज्ञानिक रूप से बताए गए कदमों को रेखांकित किया गया है क्योंकि ऐसी स्थिति में, खासकर संघर्ष और सामाजिक अशांति की स्थिति में। लेकिन हमें इन

मिड डे मील पर भारत से सीखे ब्रिटेन

भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा इन दिनों फिर दुनियाभर में है। पिछले दिनों जैसे ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने बताया कि भारत एक बार फिर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसने 2019 के बाद दोबारा ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, सबकी निगाहें भारत और ब्रिटेन की तुलना पर जा टिकीं। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बाद लगी जुबान भारत पर भी सवाल उठने लगी थी, लेकिन यहां तो आर्थिक प्रगति ने दूसरी कहानी शुरू कर दी है। जाहिर है कि देश को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब कोविड के बाद पूरी दुनिया में एक तरह की मंदी देखी जा रही है, तब आर्थिक मोर्चे पर भारत की प्रगति निरसंदेह तारीफ के काबिल है। अब जब भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ब्रिटेन से आगे है, तो कई पहलुओं पर निगाह चली जाती है। जिस देश ने भारत पर 200 साल से ज्यादा समय तक शासन किया हो, उससे उसकी तुलना होने लगे, तो निश्चित ही इसे भारत की तरक्की से जोड़ कर देखना चाहिए। ब्रिटेन में इन दिनों राजनीतिक उठापटक का दौर है। नये प्रधामंत्री के कंधे पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की मुख्य जिम्मेदारी है। बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में अप्रैल 2022 में ब्रिटेन में बिजली और गैस के दाम में 35–50 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी थी, जिससे आम लोगों पर भारी बोझ बढ़ा था। बाद में सरकार ने कार्सिल टैक्स में छूट देकर इसे कुछ

में. बीच-बीच में इसे रोका जाता रहा और अस्सी के दशक में ब्रिटिश स्कूलों में मिड डे मील योजना की विधिवत शुरुआत की गयी थी, लेकिन भोजन के नाम पर चिप्स और जंक फूड दिये जाने लगे। समय-समय पर उसका विरोध हुआ, लेकिन योजना चलती रही। साल 2005 के चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बना और उसके बाद इस योजना में काफी सुधार दिखने लगा। कोविड के दौरान योजना स्थगित रही, लेकिन जब स्कूल खुले, तो यह उस तरह से सुचारु रूप से नहीं चल पाया, जैसे इसे चलना चाहिए। फिर जब कई स्कूल इसके बदले पैसे मांगने लगे, लोगों का विरोध सड़क पर आ गया। कोरोना काल में सबसे पहले तत्कालीन ब्रिटिश चांसलर (वित्तमंत्री) ऋषि सुनक ने इस योजना का विरोध किया था। आम तौर पर मददगार लिए सांसदों को मिलने वाली भोजन सब्सिडी बंद कर दी गयी है। भारतीय के खर्च में बढ़ोतरी की वजह से इतने परेशान हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में ‘इनफ इज इनफ’ यानी अब बहुत हो चुका जैसे कैंपेन चल रहे हैं। इसके केंद्र में है ब्रिटिश स्कूलों में मिड डे मील योजना। महंगाई के कारण कई स्कूलों ने बच्चों को मुफ्त खाना देने से इनकार कर दिया है। अगर हम इसी योजना की भारत के मिड डे मील योजना से तुलना करें, तो कई बातें साफ हो जाती हैं। जहां ब्रिटेन जैसा समृद्ध देश अपने स्कूली बच्चों को खाना देने में आनाकानी करने लगा है, वहीं भारत में ब्रिटेन की पूरी आबादी के दोगुना बराबर बच्चों को

स्कूलों में हर रोज मुफ्त खाना दिया जाता है।भारत सरकार ने मिड डे मील योजना को सफल रखने के लिए हर संभव प्रयास किये हैं और इसके ानमंत्री मिल रहा है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के लोग महंगाई और जीवनयापन के खर्च में बढ़ोतरी की वजह से इतने परेशान हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में ‘इनफ इज इनफ’ यानी अब बहुत हो चुका जैसे कैंपेन चल रहे हैं। इसके केंद्र में है ब्रिटिश स्कूलों में मिड डे मील योजना। महंगाई के कारण कई स्कूलों ने बच्चों को मुफ्त खाना देने से इनकार कर दिया है। अगर हम इसी योजना की भारत के मिड डे मील योजना से तुलना करें, तो कई बातें साफ हो जाती हैं। जहां ब्रिटेन जैसा समृद्ध देश अपने स्कूली बच्चों को खाना देने में आनाकानी करने लगा है, वहीं भारत में ब्रिटेन की पूरी आबादी के दोगुना बराबर बच्चों को

की, क्योंकि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की बात होती है, तो सबसे पहले नजर उन योजनाओं पर जाती है, जिनमें आम लोगों को सुविधाएं मुफ्त मुहैया करायी जाती हैं। भारत में इन दिनों सदन से लेकर अदालत तक रेवडी कल्चर पर चर्चा है। तो क्या स्कूलों में बच्चों को मुफ्त खाना देना रेवडी कल्चर के अंतर्गत आता है, और क्या ब्रिटेन में ऐसा ही मान कर स्कूलों ने इसे बंद करने का प्रयास किया है और सरकार खामोश है? इस मामले से परदा जल्दी ही उठेगा, जब नये प्रधानमंत्री का सुचारु रूप से कार्यकाल शुरू होगा और नये वित्तमंत्री को ऐसी तमाम योजनाओं को नये सिरे से एक बार फिर समझना होगा। ऐसी स्थिति में इतना तो तय है कि मिड डे मील जैसी योजनाओं को समझने के लिए ब्रिटेन के पास भारत जैसा मजबूत उदाहरण है, जहां रेवडी कल्चर पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन कोई भी मिड डे मील योजना को उस खांचे में नहीं रखता, क्योंकि राजनेताओं से लेकर जनता तक और नौकरशाहों से लेकर अदालत तक सबको अहसास है कि दो जून की रोटी की जहोजहद कर रही आम के घरों से बच्चों को अगर शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, तो उन्हें इस तरह की सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। ब्रिटेन में इस योजना के ठीक से नहीं चल पाने का हो रहा कड़ा विरोध यह भी साबित करता है कि देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और अधिक प्रयास किये जाने की जरूरत है।—**अनुरंजन झा**

क्या जेपी जैसा कारनामा कर पाएंगे राहुल गांधी?

भारत की आवाज बन सके ऐसे किसी नेता की जरूरत अभी ज्यादा है। देश उन युवाओं का नहीं है जो खुद को हुड़दंगियों से जोड़कर देख सकें। सच यह भी है कि बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई के चलते युवा डिप्रेशन और तकलीफ से घिर रहा है। सेना में केवल चार साल की नौकरी वाली अल्पिथ को नेपाल ने भी नकार दिया है। देश से बाहर इस योजना का यह लिटमस परीक्षण था जिसमें सरकार सफल नहीं हो सकी है। युवाओं को अल्पिथ पर चलाकर किस कर्तव्य पर चलने की बात केंद्र कर रहा है। रास्तों और शहरों के नाम बदलने के स्ट्रोक्स अब पुराने हो चले हैं इससे जनता खुशहाल नहीं हो पाती। कर्तव्य की अपेक्षा अगर जनता से है तो शायद उसके सब्र का बांध अब टूट चुका है। वह अपने हिस्से का बहुत कुछ दे चुकी है, बारी अब सरकार की है उसे राहत देने की। देश में विभाजन और ६

दुवीकरण की आग कभी ठंडी न पड़े और इस पर हरेक को अब शक करना चाहिए कि राजनीतिक दल अपना उल्टू सीधा करते रह सकेंगे। हरिशंकर परसाईजी की पैनी लेखनी से ऐसे विभाजनकारी बच नहीं सके हैं। वे लिखते हैं— जब धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र चढ़कर बैठ जाता है तब गौ रक्षा करने वाले जूतों की दुकान खोल लेते हैं। ३ इधर जब कभी सरकारी की सांसें लिखते हैं— जब धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र चढ़कर बैठ जाता है तब गौ रक्षा करने वाले जूतों की दुकान खोल लेते हैं। ऐसे में देश और उसकी जनता अंदर ही अंदर एक खालीपन से भर रही है। भ्रष्टाचार और आचरण उन्हें चीर रहा है। नाउम्मीदी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे का साथ देने में लोग डर रहे हैं और डर यह भी है कि वक्त आने पर कौन हमारा साथ देगा, कर लो आज मौका है। यह भावना समाज को भीतर से खोखला कर रही है।— **वर्षा भम्भाणी मिर्जा**

आज का राशिफल

मे़ष :— उच्चस्तरीय लोगों के सानिध्य से मनोबल मजबूत होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। शासन-सत्ता से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। भौतिक सुख-साधनों की लालसा बढेगी।

वृषभ :— अत्याधिक कर्ज़भार से मन परेशान होगा। कुछ नयी आकांक्षाएं मन को उद्देलित करेंगी। रोजगार में व्यस्तता संभव। अत्याधिक पारिवारिक जिम्मेदारियां मन को बोझिल करेंगी।

मिथुन :— महत्वपूर्ण दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु मन विंचित होगा। नई दायित्व अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगे। कानूनी मामलों में कठिनाइयां संभव। तामसिक विचारों पर नियंत्रणरखें।

कर्क :— नये संबंधों के साथ आपकी सहज गुलसशीलता प्रशंसनीय है। कार्यरें को समयानुकूल पूर्ण करने का प्रयत्न करें। बिना वजह दूसरों की अलोचना न करें। आलस्य कतई न करें।

सिंह :— सगे-संबंधियों के सहयोग से उत्साह का संचार होगा। किसी रचनात्मक कार्य के प्रति रुचि पैदा होगी। पुराने संबंधों के भावनात्मक स्मरण से मन भावुक होगा। राजकीय क्षेत्र कुछ परिवर्तन के आसार बनेंगे।

कन्या :— महत्वपूर्ण कार्य के प्रति समुचित साधन व्यवस्था के लिए मन केंद्रित होगा। नई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनेंगी किंतु समुचित साधन न होने से पूर्ति में वरोध होगा। पुराने संबंध के प्रति प्रगाढ़ता बढेगी।

मित्रा

मित्रा

राजनीति व अर्थव्यवस्था में घुन है मुफ्तखोरी

दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी भी रहते हैं, जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में बसे हुए हैं। दिल्ली में ऐसे प्रवासी मजदूरों की संख्या 20 लाख से कम नहीं है। जो मजदूर अपने परिवार को साथ लाते हैं, वे भी दयनीय अवस्था में रह रहे हैं। उनके परिवार के लिए स्कूल-कॉलेजों की जरूरत है। साथ ही, बेहतर जल-मल व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सड़कों, पुलों आदि की आवश्यकता है, लेकिन इन कार्यों के लिए भारी खर्च की जरूरत होती है। देखा जा रहा है कि खर्च के अभाव में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार विकास और रखरखाव के लिए भी ६ ान नहीं जुटा पा रही है। साल 2015 में सत्ता संभालने के बाद से दिल्ली सरकार कोई नया स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पलाइओवर आदि बना नहीं पायी। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय व राजस्व शेष भारत से काफी अधिक है और लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस राजस्व को मुफ्त बिजली, पानी और यातायात में खर्च कर देने के कारण आवश्यक नागरिक सुविधाों हेतु धना का अभाव होता जा रहा है। दिल्ली का कुल राजस्व 2021–22 के लिए 53070 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो सभी राज्यों के राजस्व का तीन प्रतिशत है। बढ़ते राजस्व के साथ-साथ दिल्ली सरकार का मुफ्त बिजली, पानी, यातायात पर खर्च भी बढ़ता गया। मुफ्त बिजली पर खर्च 2015–16 में 1६39 करोड़ रुपये था, जो 2021–22 में 2968 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वर्ष 2022–23 के लिए विद्युत विभाग ने दिल्ली सरकार से बिजली सब्सिडी हेतु 3200 करोड़ रुपये की मांग की है।

समझा जा सकता है कि दिल्ली सरकार द्वारा बिजली मुफ्त करने के नाम पर बजट पर बोझ बढ़ता जा रहा है। पानी के बिल को शून्य करने की कवायद में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा और कर्ज दोनों बढ़ रहे हैं। केजरीवाल सरकार के पहले तीन साल में बोर्ड का घाटा 2015–16 में 220।19 करोड़ से बढ़ता हुआ 2018–19 में 6६3 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था।

दिल्ली सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जल बोर्ड को 41000 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये हैं। जल बोर्ड की बदतर स्थिति का अंदाजा धीमे विकास कार्यों और लचर जल व्यवस्था सेलगाया जा सकता है। विपक्षी दल जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते रहे हैं। महिलाओं को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा एक अन्य मुफ्तखोरी वाली स्कीम है। सरकार द्वारा लोगों को मुफ्त की स्कीमों से हजारों करोड़ रुपये का घाटा होता है। स्वभाविक है कि सीमित संसाधनों के चलते इस मुफ्तखोरी की नीति से सरकारी राजस्व पर दबाव बनता है और कई आवश्यक खर्चों को टालना पड़ता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को 20 नये कॉलेज देने, फ्री वाई-फाई उपलब्ध कराने, 20000 सार्वजनिक टॉयलेट बनवाने, महिला सुरक्षा फोर्स बनाने, तीन लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, आठ लाख नौकरियों के सृजन, दिल्ली कौशल मिशन द्वारा हर साल एक लाख युवकों को कौशल प्रशिक्षण समेत 69 ऐसे वादे किये थे, जो या तो वादे रह गये या जिनमें प्रगति अत्यंत धीमी रही। इन वादों को पूरा न कर पाने के पीछे मुख्य कारण ६ ानाभव है।गौरतलब है कि इस सरकार से पहले 1999–2000 और 2014–15 के बीच 15 साल में पूंजीगत व्यय 510।5 करोड़ रुपये से बढ़ कर 7430 करोड़ रुपये हो गया (प्रति वर्ष वर्षदि 19।6 प्रतिशत रही), जो आप सरकार के पहले पांच साल में 7430 करोड़ रुपये से बढ़ कर मुश्किल से 1१549 करोड़ रुपये ही पहुंची (वार्षिक वर्षदि मात्र 9।2 प्रतिशत रह गयी)। यदि कहा जाए कि सरकारी खजाने से पैसा देकर बिजली ‘गरीबों’ के लिए मुफ्त या कम कीमत पर उपलब्ध करायी जा रही है, तो यह सही नहीं होगा। वर्ष 2021–22 में दिल्ली में जहां चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 4,01,9८2 रुपये प्रति वर्ष है, वहां 54।5 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 43।2 लाख लोगों को या तो मुफ्त या आधी कीमतों पर बिजली दी जा रही है। इससे नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं और कर्ज बढ़ रहा है, तो उसे औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। यही नहीं, 5।3 लाख घरों को प्रतिमाह 20 हजार लीटर पानी भी मुफ्त दिया जा रहा है। दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी के लालच से राजनीतिक लाभ उठाने वाली आम आदमी पार्टी ने अब दूसरे राज्यों में भी ऐसे लालच देना शुरू किया है। समझना होगा कि मुफ्तखोरी की यह राजनीति देश की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था के लिए अमंगलकारी है, जिसे आम सहमति से रोकने की जरूरत है।

केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर चक मार्गों के निर्माण की प्रक्रिया हुती तेज

प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गांवों के अतिक्रमित चक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उनका निर्माण मनरेगा से कराते जाने के निर्देशो पर त्वरित गति से कार्यवाही की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अतिक्रमित चक मार्गों के खाली हो जाने से जहां गांवों में रास्तों को लेकर आपसी विवादों में विराम लगेगा, वहीं किसानों को कृषि कार्यों हेतु अपने खेतों में आने–जाने में सुगमता होगी,फलतरुउनकी फसल उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा,यही नहीं बाढ़, वर्षा या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त चकमार्ग भी इस मुहिम के तहत मजबूत बन जायेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्टर चकमार्गों, तालाबों व सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के कारण आपसी रंजिश व मारपीट की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे कृषि की उत्पादकता को कम करके ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं



प्रभावित होती है। ग्रामीण परिवेश में इन समस्याओं के निराकरण हेतु आ्ारभूत ढांचों के विकास एवं विवादों के समाधान हेतु चक मार्गों का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है। इस कार्य को मुकम्मल अन्जाम देने हेतु ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी

स्वरूप पैमाइश, चिन्हांकन किया जाए। चकबन्दी में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होते ही वहाँ के चकरोड भी प्राथमिकता पर बनवाने का कार्य किया जाए।चिन्हांकित कार्यों को मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राक्ि गानों के अनुसार कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए नियमानुसार अभियान चलाकर चिन्हांत चकमार्गों पर कार्य प्रारम्भ कराया जाए। नव निर्मित सड़कों के किनारों वरहद स्तर पर वक्षारोपण की कार्यवाही की जाए, जिससे पर्यावरण में सुधार हो सकें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चक मार्ग निर्माण हेतु संबंधित विभागों, आम जनमानस व अन्य स्टेक होल्डर्स को प्रोत्साहित कर यथावश्यक सहयोग लिया जाए।— आई०जी०आर०एस० व संपूर्ण समाधान दिवस से आच्छादित प्रकरण तथा चकबंदी प्रक्रिया से बाहर जा रही ग्राम पंचायतों में चिन्हित सार्वजनिक स्थलों (यथा— चकरोड, एवं चकबन्दी के सहयोग से भूमि एवं राजस्व अभिलेखों में दर्ज सेक्टर मार्गों, चकरोडों को वरहद रूप से अभियान

योगी सरकार का बड़ा आदेश, यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों का नाम उर्दू में भी लिखा जाएगा

प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने सरकारी अस्पतालों के नाम अब हिंदी के साथ–साथ उर्दू में भी लिखे जाने के अहम आदेश जारी किया है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी साइनबोर्ड और नेमप्लेट लिखे जाएंगे। इस पर चर्चा शुरू हो गई है। उन्नाव निवासी मोहम्मद हारुन की एक शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। जारी आदेश में साफ किया गया है कि प्रदेश में अब हिंदी के साथ उर्दू में भी अस्पतालों के नाम लिखे जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों और सीएचसी– पीएचसी के भवनों के नाम हिंदी के साथ उर्दू में भी होंगे। स्वास्थ्य निदेशक की ओर से इस संबंध 1 में सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में भवनों के नाम के साथ–साथ चिकित्सकों और कर्मचारियों के नाम और पदनाम भी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखने के निर्देश दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के सभी 167



सरकारी जिला अस्पतालों, 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 2934 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम हिंदी के साथ–साथ उर्दू में भी लिखा जाएगा। दरअसल यूपी ने यूपी राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 के माध्यम से दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया था, जिसने यूपी

लखनऊ जिला अंडर-23

एथलेटिक्स चौपियनशिप

12 सितंबर को

लखनऊ। लखनऊ जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में 12 सितंबर को लखनऊ जिला अंडर–23 पुरुष व महिला एथलेटिक्स चौपियनशिप केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होगी। लखनऊ जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव बीआर वरुण के अनुसार चौपियनशिप में भाग लेने के इच्छुक एथलीटों को की उम्र एक नवंबर 1999 से 31 अक्टूबर 2002 के मध्य होनी चाहिए। उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना आधारकार्ड लाना हो गा। लखनऊ ज़िला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव बीआर वरुण ने बताया कि इच्छुक एथलीटों को आयोजन स्थल पर सुबह 8 बजे बजे संपर्क करना होगा। उन्होंने बताया कि इस चौपियनशिप के माध्यम से से चयनित लखनऊ जिला टीम आगामी 15 व 16 सितंबर को गोरखपुर में होने वाली यूपी स्टेट अंडर–23 पुरुष व महिला एथलेटिक्स चौपियनशिप में भाग लेगी। चौपियनशिप के बारे में अधिक जानकारी के लिए बीआर वरुण (9415027942) से संपर्क कर सकते हैं।

अखिलेश के बयान पर मायावती के भतीजे का पलटवार, बोले, खुद तो एसी कमरे में सोते हो



प्रयाग दर्पण संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती पर भाजपा के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी ही जेल में कैद हैं और जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। इसे लेकर बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे व पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। आकाश आनंद ने

अखिलेश पर तंज कसते कहा कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर हैकुर ये बात वो कह रहे हैं, जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आजतक ये नहीं समझ पाए कि वो एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते? जिनके कार्यकांत ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वे दो बजे सोकर क्यों उठते हैं, वो अखिलेश यादव न जाने किस भ्रम में हैं। बता दें कि बीते दिन अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साध कहा था कि मायावती बीजेपी के

त्यागी समाज की योगी सरकार को धमकी, कहा, सुनवाई नहीं हुई तो बजा देंगे ईट से ईट



नोएडा। नोएडा के श्रीकांत त्यागी मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में एक वेब पोर्टल से बातचीत में त्यागी समाज जिला अध्यक्ष शिवकुमार त्यागी ने कहा, ‘अगर श्रीकांत से फर्जी मुकदमें नहीं हटाए गए तो वो सरकार की ईट से ईट बजा देंगे।’ सहारनपुर में डीएम ऑफिस के सामने त्यागी समाज के बैनर तले त्यागी महासभा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि श्रीकांत

त्यागी और उसके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। त्यागी समाज की ओर से ये बात भी बताई गई कि त्यागी परिवार पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए पहले भी त्यागी समाज ने जिलाधिकारी के माध्यम से 10 अगस्त को मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भिजवाया गया था, लेकिन उस ज्ञापन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसकी वजह से श्रीकांत त्यागी का पूरा परिवार अभी भी तकलीफ झेलने को विवश है। अपने आंदोलन के दौरान त्यागी समाज काफी उग्र दिखाई दिया। त्यागी समाज का कहना था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो सरकार की ईट से ईट बजा देंगे। वहीं अर्जुन सिंह त्यागी ने मीडिया से बातचीत में बताया, ‘हम लोग घरने पर इसलिए बैठे हैं कि श्रीकांत त्यागी पर गंस्टर लगाया गया है और उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर श्रीकांत त्यागी के परिवार का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो वो सरकार को आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे।’

विद्युत उपकेन्द्र सेक्टर छह जानकीपुरम विस्तार में लगा वैक्सीनेशन कैंम्प

लखनऊ। जनविकास महासभा ने आज यहां विद्युत उपकेन्द्र, सेक्टर–छह, जानकीपुरम विस्तार में कोविड–19 वैक्सीनेशन कैंम्प का आयोजन किया। जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बड़ चक्कर हिस्सा लिया और वैक्सीनेशन लगवाया। परी पुस्तक के सहयोग से लगाये गये इस शिविर के शुभारम्भ मौके पर विद्युत उपकेंद्र के अधिशासी अभियंता आदर्श कुमार कौशल, लखनऊ जनविकास महासभा एवं लक्ष्य जन कल्याण समिति जानकीपुरम विस्तार के अध्यक्ष एसके बाजपेई, सामाजिक संस्था सोक्ट के अध्यक्ष डॉ. आरम दयाल, जनविकास महासभा के अध्यक्ष पंकज कुमार तिवारी ‘एडकोरेट’ अध्यक्ष मंत्री, अजय कुमार यादव एवं पण्डित महेंद्र मिश्रा, वित्त योगानन्द पांडेय बैठक में मौजूद। कहा जा रहा कि अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन ना मिलने के बाद से ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा से बचाव के उपाय और वैक्सीनेशन के महत्व के प्रति जागरूक किया।

सूखे से निपटने के लिए योगी सरकार कर रही सर्वे का छलावा : अखिलेश यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जनता के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सूखे की छाया मंडरा रही है और किसानों को मुआवजा देने की जगह योगी सरकार अभी तक सर्वे का छलावा कर रही है। अखिलेश ने भाजपा की वादाखिलाफी के सबूत देते हुए कहा कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री योगी ने किसानों से मुफ्त सिंचाई का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा सरकार अपने वादे से मुकर गई। प्रदेश में सूखे की छाया मंडरा रही है।

किसानों को मुआवजा देने की जगह भाजपा सरकार अभी तक सर्वे का छलावा कर रही है। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने का वादा भी भाजपा ने नहीं निभाया। भाजपा सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। जनता से वादाखिलाफी करने को भाजपा का वास्तविक चरित्र बताते हुए अखिलेश ने कहा कि चुनाव के समय किसानों को सम्माननिधि दी गई थी, लेकिन अब उनसे वसूली हो रही है। अखिलेश के हवाले से पार्टी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि जनता को धोखे में रखने के लिए नये नये वादों और जुमलों की हेराफेरी करने में भाजपा को महारथ हासिल है। पवित्र मां गंगा और यमुना नदी से भी भाजपा धोखा करती है। युवाओं को तो छलती ही रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की इन हरकतों से जनता तंग आ चुकी है। अब जनता भाजपा को आगे बर्दाश्त नहीं करेगी। उप्र के अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने से पहले ही जनता भाजपा को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ही सबक सिखा देगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की हकीकत भी भाजपा के दावों से बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि उद्योगधंधे े फाइलों में चल रहे है। नौकरी के नाम पर नौजवानों को सिर्फ भटकया गया है। परीक्षाओं में धांधली आम बात हो गई है। युवा बेरोजगारों की फौज को राष्ट्र की प्रति और विकास में भागीदारी से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है।

संक्षिप्त खबरे

उत्तर प्रदेश महोत्सव का पोस्टर रिलीज

लखनऊ। सश्रजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित किये जा रहे 7वें उत्तर प्रदेश महोत्सव का पोस्टर शुक्रवार को रिलीज किया गया। ये पोस्टर मंत्री राकेश सचान द्वारा उनके कैम्प कार्यालय में रिलीज किया गया। महोत्सव आठ अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2022 तक कथा मैदान, बंगला बाजार चौराहे के पास, आशियाना में होगा। इस अवसर पर सश्रजन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ अमित सक्सेना, आयोजन समिति के सदस्य अजीत कुशवाह, रोहित कश्यप एवं शैलेंद्र मोहन उपस्थित रहे।

योगी ने संतकबीरनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे का लिया संज्ञान

लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतकबीरनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल पहुंचने और राहत–बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

चाकू गोदकर युवक का मर्डर,पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया

लखनऊ। सरोजिनी नगर के दरोगा खेड़ा स्थित छोटी नहर के पास शुक्रवार सुबह एक युवक का शव मिला। शव पर चाकू के वार के निशान थे। परिजनों ने हत्या के पीछे उसके ही बहनोई का हाथ बताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुल्लाही खेड़ा सोयायटी रोड निवासी वीरेंद्र कुमार के 25 वर्षीय बेटे रोहित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वह परिवार के साथ सरोज कुमार पाल के मकान में किराए पर रहते हैं। परिजनों के मुताबिक, गुरुवार देर रात किसी का फोन आने के बाद रोहित घर से निकला था। जिसके बाद नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह आसपास के लोगों ने दरोगा खेड़ा स्थित छोटी नहर में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। शिनाख्त होने पर पुलिस ने घर पर सूचना दी। इंस्पेक्टर का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इसके बाद कारंवाई की जाएगी। संतोष कुमार आर्य के मुताबिक, घटनास्थल से गुजर रहे एक राहगीर ने रोहित से अंत समय में बातचीत करके मोबाइल से रिकॉर्डिंग की की है। जिसमें रोहित ने बताया कि उसको जीजा ने मारा है। फिलहाल मृतक के पिता द्वारा तहरीर दी गई है। मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस घटना की जानकारी का बाद आरोपी और उससे दो साथियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जिससे हत्या में शामिल लोगों के विषय में सही जानकारी हो सके।

ताइक्वाण्डो चैम्पियनशिप में सी.एम.एस. छात्रों ने जीते दो गोल्ड मेडल

लखनऊ। सिटी मोन्टेसी स्कूल, चौक कैम्पस के प्रतिभाशाली छात्रों हर्षिता यादव एवं हमजा सिद्दीकी ने 18वीं डिस्ट्रिक्ट इण्टर–स्कूल ताइक्वाण्डो चैम्पियनशिप में दो गोल्ड मेडल अर्जित कर विद्यालय का नाम गौरवाचित किया है। प्रतियोगिता में हर्षिता यादव ने 47.5 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मेडल जीता है जबकि हमजा सिद्दीकी ने 55.5 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मेडल जीता। सी.एम.एस. संस्थापक डा. जगदीश गांधी ने विद्यालय के इन दोनों होनहार छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन–सम्पर्क अधिकारी हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि इस चैम्पियनशिप में लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के छात्र खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर ताइक्वाण्डो प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया तथापि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सी.एम.एस. के इन प्रतिभाशाली छात्रों ने अपनी खेल प्रतिभा, चुस्ती–फूली, कौशल तथा दमखम के बलबूते गोल्ड मेडल अर्जित कर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के संकेत दिये है। श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. छात्र न सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र में अपितु खेलों व समाज के अन्य बहुतेरे क्षेत्रों में भी विद्यालय का नाम राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं क्योंकि सी.एम.एस. अपने छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ उन्हें खेलों व अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए भी विशेष रूप से तैयार करने में पूरे मनोयोग से संलग्न है।

पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा

लखनऊ। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने करीब 23 महीने बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। सिद्दीकी कप्पन को पांच अक्तूबर, 2020 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस यूएू ललित व जस्टिस एस. रवीन्द्र मट्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से कप्पन की याचिका पर पांच सितंबर तक जबाव देने को कहा था। दरअसल, हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूपीएी) की धाराएं लगाई गई हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

आइटा पुरुष प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट 10 सितंबर से' लखनऊ।

उन्नाड टेनिस अकादमी के तत्वावधान में आइटा पुरुष प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन आगामी 10 से 16 सितंबर तक होगा।

रॉ मेटेरियल को बनाने के पश्चात इंडस्ट्री में रीसेल किया जाएगा।

प्रयागराज। मण्डलायुक्त श्री विजय विश्वास पन्त की अध्यक्षता मे प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 18वीं बोर्ड बैठक कार्यालय स्थित गांधी सभागार में संपन्न हुई जिसमें कुछ नई परियोजनाओं को बोर्ड द्वारा हरी झंडी मिली। रसूलदाह घाट पर बनाए जा रहे हरित शवदाह गृहों की संख्या बढ़ा दी गई है अब तीन की बजाय वहां पर 9 हरित शवदाह ग्रह बनाए जाएंगे। हरित शवदाह ग्रह नॉर्मल शवदाह गृहों की तुलना में सिर्फ एक तिहाई ईंधन का प्रयोग करते हैं एवं इनमें वायु प्रदूषण का बराबर होता है।इसी क्रम में जनपद में 6 विभिन्न स्थानों पर मेटैरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। यह फैसिलिटीज ठोस अपशिष्ट को प्रोसेस करके उनमें से पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एवं क्लिंक्स की रॉ मटेरियल बनाने में उपयोगी होगी। इन रॉ मेटेरियल को बनाने के पश्चात इंडस्ट्री में रीसेल किया जाएगा। क्लिंक्स धातु मल या छोटी ईंट के टुकड़े जैसा होता है जिसका उपयोग फर्श के पत्थर के रूप में किया जाता है।बैठक में कुछ अन्य नयी परियोजनाओं के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई जिसमें स्मार्ट वेंडिंग जोन, स्मार्ट स्कूल, हेल्थ ए0टीएम0, नगर निगम जोनल कार्यालयों का जीर्णोधार, शहर में स्मार्ट बिन लगाना तथा एक वृहद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना भी शामिल रहे।बैठक में नगर आयुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रयागराज स्मार्ट सिटी लि0 श्री चन्द्र मोहन गर्ग समेत सभी संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

उप शिक्षा निदेशकध्प्राचार्य डायट प्रयागराज श्री राजेंद्र प्रताप के अध्यक्षता में चार दिवसीय सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना निर्माण कार्यशाला संपन्न।

प्रयाग दर्पण संवाददाता

प्रयागराज। आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज में चार दिवसीय सूक्ष्म शिक्षण एवं पाठ योजना निर्माण कार्यशाला के प्रशिक्षण का समापन डायट प्राचार्य व वरिष्ठ प्रवक्ता श्री शिव नारायण के आशीर्चन के पश्चात हुआ। कार्यशाला का संयोजन डायट प्रवक्ता श्री वीरभद्र प्रताप, डॉ. अंबालिका मिश्रा एवं डॉ. राजेश पांडेय द्वारा हुआ। कार्यशाला में सूक्ष्म शिक्षण व आदर्श पाठ्य योजना बनाने के नियम, सिद्धांत व अभ्यास से डी.एल.एड. छात्रा् यापकों को परिचित कराया गया।

इसके बाद छात्र अध्यापकों को प्रायोगिक कार्य हेतु इंटरनिशप पर जाने से पूर्व बृहद पाठ्यक्रम शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजना का निर्माण कर प्रदर्शन के माध्यम से छात्राध्यापको द्वारा प्रस्तुतीकरण कराया गया। कार्यशाला मे उप शिक्षा निदेशकध्प्राचार्य डायट ने अपने अनुभव से छात्राध्यापकों को पाठ्य योजना के तकनीकियों से परिचित कराया। वरिष्ठ प्रवक्ता श्री शिव नारायण

प्रकार से करने पर बल दिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती रत्ना यादव, श्रीमती ममता यादव, प्रवक्ता कुलभूषण मौर्य, वरिक्ता कुशवाहा, विवेक त्रिपाठी, रिचा राय, नीलम चतुर्वेदी, मनीषा प्रकाश, विबनम के साथ डी.एन. प्रवक्ता श्री पंकज कुमार यादव प्रशिक्षुओं को अपने दायित्वों के निर्वहन ठीक

एल.एड. प्रशिक्षुओं– 2021 के विपिन कुशवाहा, विनय, इमरान, समेत सभी प्रशिक्षुओं की सहभागिता विशेष रहा। कार्यक्रम के तकनीकी सहयोगी के रुप में श्री दिनेश कुमार व अनिल पांडेय का विशेष योगदान रहा तथा कार्यक्रम का संचालन श्री संजय यादव द्वारा किया गया।

बाराबंकी। पुलिस प्रशासन द्वारा भूमण्डल अभियुक्त गैंगलीडर की अचल सम्पत्ति कुलित सम्पत्ति 20 लाख 97 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। थाना कोतावाली नगर पर पंजीकृत मो०अं०सं० 5525/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गैंग लीडर संजय सिंह सिंघला पुत्र पुरुशोत्तम दास सिंघला निवासी म०नं०-624 वी/159 विवाईपुर्व विजयपुर खण्ड-2, गोमती नगर जनपद लखनऊ सिंघला रजिडेंसी नामक कम्पनी बना कर लोगों को प्लाट मकान की रजिस्ट्री किए जाने तथा सम्बन्धित कर्तव्य को कब्जा दिये जाने के बाद उन्हीं प्लाटधम्कान को पुनरु अपने कब्जे में लेने के लिए भूस्वामी द्वारा कराये गये निर्माण को हटाकर फिर से अपने कब्जे में लेने के बाद रजिस्ट्री करए व्यक्ति को पैसा वापस न करने जैसा अपराध कर एवं रूप से धनोपाई करण कर स्वयं एवं परिजनो के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित करी गई । बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अथेव रूप से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं संजय विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।अभियुक्त गैंगलीडर संजय सिंह सिंघला पुत्र पुरुशोत्तम दास सिंघला निवासी म०नं०-624 वी/159 विजयपुर विविष खण्ड-2, थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ कुर्क सम्पत्ति कुलित लगभग बीस लाख सत्तावन हजार एक सौ दस रुपये की है जिसमें के०डीटी प्लाजा राम राम बैंक चौराहा अलीगंज लखनऊ स्थित दुकान कीमत लगभग 20.57,110 रुपये है तथा अभियुक्त का अपराधिक इतिहास भी है जिसमें उसके विरुध्द थाना कोतावाली नगर जनपद बाराबंकी बौर थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ में कल आठ महकमें दर्ज है ।